[Shri Kartar Singh.]

majority of the services in PEPSU have vested interests there, and my hon. friend has not been able to refute that charge.

MR. CHAIRMAN: Would the hon. Minister like to speak?

SHRI M. C. SHAH: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Patiala and East Punjab States Union for the service of a part of the financial year 1953-54, as passed by the House of the People, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bil.

Clause 1, the Title and the Enacting Formula were added to the Bill.

SHRI M. C. SHAH: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

THE APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1953.

THE DEPUTY MINISTER FOR FINANCE (SHRI M. C. SHAH): Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of a certain further sum from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1952-53, as passed by the House of the People, be taken into consideration."

Sir, this does not require a speech as the House is well aware that already we have passed an Act for the distribution of the Excise Duty as recommended by the Finance Commission. And when the Budget was introduced, it was not possible to make provision for this sum and therefore now by this Appropriation Bill we want to make a provision for the sum to be given to all the States as provided for in the Act that we have already passed.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of a certain further sum from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1952-53, as passed by the House of the People, be taken into consideration."

(*No hon. Member rose to speak.*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of a certain further sum from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1952-53, as passed by the House of the People, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We take up now the clause-by-clause consideration of the Bill. No amendments.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Title and the enacting formula were also added to the Bill.

SHRI M. C. SHAH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

SHRI KANHAIYALAL D. VAIDYA (Madhya Bharat):

श्री कन्हैयालाल डी० वैद्य (मध्य भारत) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने रखा गया है उसके अन्तर्गत जिन जिन राज्यों

को जो रकम दी जाने वाली है, वह हमारे सामने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट (Report of the Finance Commission) के रूप में पहले ही सदन के सामने आ चुकी है। इस समय हम इस पर अन्तिम रूप में इस वर्ष की रकम की स्वीकृति के लिए विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में संक्षेप में मध्य-भारत राज्य के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस कमीशन ने मध्य भारत के विषय में जो सिफारिशें की है उसके अन्तर्गत २.२९ की रकम दी जानी स्वीकृत हुई है। जब हम मध्य भारत के विषय में कहते है तो हमें वहां की स्थिति का ख्याल आ जाता है, वहां के शासन का जो स्टैण्डर्ड. (standard) है उसको देखते हुए जो रकम फाइनेंस कमीशन ने उस राज्य के लिए दी है वह बहुत ही कम मालूम होती है। इस रकम के विषय में मध्य भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार और कमीशन से ज्यादा रकम बढ़ाने के बारे में मांग की है।

मध्य भारत की आबादी का एक तिहाई हिस्सा पिछड़ा हुआ हिस्सा है जो शताब्दियों से शोषित और पीड़ित रहा है। इन पिछड़े हुए लोगों के पास न रहने के लिए मकान है न पहनने के लिए वस्त्र है और न खाने के लिए ही इनको अच्छी तरह से मिलता है। वहां करीब ९ लाख लोग इस वर्ष दुष्काल की हालत में रहते है जिनकी सहायता करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। उन लोगों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता की बहुत ही आवश्यकता है और इन बातों पर केन्द्रीय सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। जो रकम फाइनेंस कमीशन ने मध्य भारत के लिए स्वीकृत की है अगर उसकी ओर केन्द्रीय सरकार ध्यान दे और उसको बढ़ा दे तो उस राज्य की गरीब जनता का बहुत उत्थान हो सकता है। इसके साथ साथ वहां की शिक्षा और मेडिकल व्यवस्था में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय वहां पर इन चीजों की बहुत ही कम व्यवस्था है और बहुत ही पिछड़ी हालत में है। मुझे आशा है कि सरकार वहां की इस पिछड़ी हुई हालत की ओर अवश्य ध्यान देगी और कमीशन ने जो सिफारिश की है, उस रकम को और ज्यादा बढ़ा देगी। जब हम सौराष्ट्र और ट्रावनकोर की रकम को देखते है जोकि फाइनेंस कमीशन ने इन प्रान्तों के लिए दी है और उसको मध्य भारत की रकम से मिलाते है तो हमें मध्यभारत का क्लेम (claim) ज्यादा रकम मांगने का उचित मालूम होता है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूं और आश करता हूं कि वह मध्य भारत की इस उचित मांग की ओर अवश्य ध्यान देंगे और इसके लिए व्यवस्था करेंगे।

[For English translation, *see* Appendix IV, Annexure No. 90.]

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the hon. Minister.

SHRI M. C. SHAH: I do not think, Sir, anything can be done. This question was discussed fully by this House and practically the Finance Commission's recommendations are in the nature of an award which has been accepted in toto by the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.